There was one IAS officer whose tenure has come to an end on 21.7.1996.

(ii) *Indian Institute of Public Administration (IIPA):*

Nil

(iii) *Institute of Applied Manpower Research:*

Nil

(iv) *National Institute of Rural Development:*

Two IAS fficers are at present in position and one IAS officer has recently been approved.

(b) and (c) Appointments of IAS officers are made either under the Central Staffing Scheme after following the prescribed procedure laid down therein, or under the relevant recruitment rules prescribed or under the provisions of rule 6 of the IAS (Cadre) Rules 1954, as appropriate to the case.

जम्मू और कश्मीर में विकासात्मक योजनाओं का मूल्यांकन

1892. **श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में विकास कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के बेहतर प्रबन्धन और सुचारू कार्यान्वन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के कई दल राज्य का दौरा कर चुके हैं तथा विकास कार्यों का स्वयं निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने विकास योजनाओं और कार्यों के निष्पादन कार्य को कुल मिला कर संतोषजनक पाया है। योजना गतिविधियों का कड़ा पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए ताकि निधियों की चोरी को न्यूनतम किया जा सके, राज्य सरकार ने जिला विकास आयुक्तों के नेतृत्व में विभिन्न सेक्टरों में बड़े कार्यों का मौके पर मूल्यांकन करने हेतु जिला स्तर पर प्रत्यक्ष सत्यापन समितियां भी गठित की हैं। केन्द्र और राज्य सरकार के इन संयुक्त प्रयासों से पर्यवेक्षण प्रणाली को नया रूप देने और जवाबदेही को कड़ाई से लागू करने में पर्याप्त मदद मिली है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में समांतर बॉटलिंग संयंत्रों के लिए लाइसेंस

1893. **श्री राघवजी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में समांतर बॉटलिंग संयंत्र शुरू करने के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या कितनी है और उन व्यक्तियों और राज्यों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने एक सिलेंडर का कोई मूल्य निर्धारित किया है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के रसोई गैस सिलेंडरों की दरों में कोई विसंगति है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में अब तक कितने संयंत्र शुरू किये गए हैं और कितने संयंत्र कार्य कर रहे हैं तथा उनमें से कितने संयंत्र बन्द होने के कगार पर हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच करने के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की थी; और

(च) क्या समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत एल पी जी भरण संयंत्रों की स्थापना के लिए 322 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इन्हें अभिन्यास अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अब तक इनमें से 100 इकाइयों को प्रचालन लाइसेंस प्रदान कर दिए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निजी क्षेत्र में एल पी जी भरण

संयंत्रों के लिए लाइसेंस देने और इनके प्रचालनों की निगरानी नहीं करता है।

(ख) और (ग) समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत आयातित एल पी जी पर सरकार का कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसे समानांतर विपणनकर्ताओं द्वारा आयात मूल्य एवं मांग और पूर्ति की स्थिति के आधार पर नियत किये गये बाजार निर्धारित मूल्यों पर बेचा जर रहा है। मांग और पूर्ति की इस स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विपणन की जा रही एल पी जी का मूल्य विभिन्न तथ्यों के आधार पर नियत किया जाता है, जैसे—उत्पाद मिश्रण, उत्पादन और आयात की लागत, वितरण लागतें, परस्पर राजसहायता का व्यवहार्य घटक।

(घ) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के अनुसार इन 100 इकाइयों में से किसी भी इकाई ने अपने संयंत्रों को बंद करने के बारे में सूचना नहीं दी है।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस संबंध में जांच करने के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन नहीं किया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Promotion of Agro-Forestry and Medicinal Plants in Maharashtra

1894. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have introduced Technology Development, Training and Extension Scheme for the promotion of agro-forestry and medicinal and herbal plants for wastelands development in Maharashtra;

(b) if so, what are the details there of; and

(c) the number of projects presently being taken up in the State, district-wise, and their position as on date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) and (b) A Central Sector Scheme of "Technology Development, Extension & Training for Wastelands Development in non-forest areas" is under implementation from the year 1994-95 in the country, including Maharashtra State. Under this Scheme, Technology Development projects including agroforestry system models are promoted and depending upon the suitability and needs of the local conditions, the medicinal and herbal plants are at times integrated. Further, 100% per cent Central Grant is admissible for implementing projects on lands owned by Governments/Government Institutions/ Government Undertakings including Universities and non-profit making Agencies or the Village Panchayats from which the unsufructs will flow to the community. For projects on land belonging to private farmers/Corporate Sectors, the cost is shared in a 60:40 ratio between the Government and the farmers/Corporate Bodies. The objectives of the Scheme include: (i) to operationalise appropriate, cost effective and proven technologies for development of various categories of wastelands specially problem lands affected by soil erosion, land degradation, salinity, alkalinity, waterlogging etc., (ii) to implement location specific pilot project as demonstration models for development of wastelands on a sustainable basis replicable to larger areas, (iii) to take up pilot projects for development of wastelands through land based activities including pisciculture, duckery, bee keeping, etc., (iv) to disseminate research findings about new and appropriate technologies and the application of such technologies for promoting wastelands development.

(c) Presently under Technology Development, Extension & Training Scheme, three Central Sector projects are under implementation in Maharashtra. The details are given in Statement.